

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी:- कृष्णपाल सिंह चौहान(आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 2/2019

दायर दिनांक 28.08.2019

निर्णय दिनांक 26.2.2021

सुरेश उर्फ जसवंत पिता छगनलाल पण्ड्या ब्राम्हण, निवासी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर हाल निवास अमेरिका जरिए अधिकार पत्रधारी सनद कुमार पिता जगन्नाथ जी पण्ड्या जाति ब्राम्हण निवासी धम्बोला त. सीमलवाडा जिला डूंगरपुर – निगरानीकर्ता / प्रार्थी

बनाम

- 1 सुखलाल पिता छगनलाल पण्ड्या, जाति ब्राम्हण, निवासी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
- 2 ग्राम पंचायत सीमलवाडा जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत सीमलवाडा

– रेस्पोंडेंट / विपक्षी

निगरानी बनाराजगी

निगरानी अर्न्तगत नियम 272 राज. पंचायत जनरल रूल्स 1961

ग्राम पंचायत सीमलवाडा पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 बाबत

अधिवक्ता-प्रार्थी की ओर से श्री नरेश जोशी एडवोकेट

अधिवक्ता विपक्षी सं. एक-श्री धर्मेन्द्र गेहलोत, श्री लक्ष्मणसिंह सिसोदिया एडवोकेट

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सुरेश उर्फ जसवंत द्वारा अपने अधिकार पत्र धारी के माध्यम से यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की जिसमें उल्लेखित तथ्यों के आधार पर सुरेश उर्फ जसवंत तथा विपक्षी सुखलाल आपस में भाई है तथा उनके पिता द्वारा कय सम्पत्ति मौजा सीमलवाडा में स्थित है। जो पूर्व से पश्चिम 90 फीट तथा उत्तर से दक्षिण 47 फीट है, जिसका कुल क्षेत्रफल 4230 वर्ग फीट है। उपरोक्त सम्पत्ति के पूर्व दिशा में पीठ डूंगरपुर मार्ग, पश्चिम दिशा में मोहल्ले का रास्ता, उत्तर में शैलेश शाह का मकान होना तथा दक्षिण में 9 फीट की गली होना अंकित किया है। निगरानीकर्ता द्वारा अंकित किया गया कि उपरोक्त सम्पत्ति निगरानीकर्ता व विपक्षी के पिता छगनलालजी द्वारा ठीकाना सीमलवाडा से कय की गई थी। साथ ही यह भी उल्लेखित किया कि निगरानीकर्ता के विदेश में निवास के दौरान विपक्षी सुखलाल व अन्य भाई नवनीतलाल द्वारा दिनांक 11.9.2000 को इस भूमि पर निर्माण की स्वीकृति भी प्राप्त की थी। विपक्षी सुखलाल यह जानता था कि उपरोक्त भूमि, निगरानीकर्ता व विपक्षी के पिता की कय शुदा भूमि है तथा विपक्षी सुखलाल तथा निगरानीकर्ता व अन्य भाई नवनीतलाल जिसकी मृत्यु हो चुकी है, सभी इस संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन विपक्षी सुखलाल द्वारा छिपे तौर पर ग्राम पंचायत सीमलवाडा से पट्टा सं. 280 मिसल नम्बर 11 तारीख दायर 13/6/2005 संकल्प दिनांक 20/7/2005 पट्टा जारी करने की दिनांक 21/7/2005 के जरिए नियम 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत पट्टा जारी करवा लिया है जो नियम विरुद्ध है तथा उपरोक्त पट्टे की जानकारी दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डूंगरपुर

प्रकरण संख्या 02/2019 अनवान श्री सुरेश उर्फ जसवंत बनाम सुखलाल
निवासी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर



1/8/2019 को निगरानीकर्ता को हुई। क्योंकि सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष जो विपक्षी सुखलाल द्वारा वाद पेश किया था, उसमें उसके द्वारा उपरोक्त दिनांक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टे के दस्तावेज पेश किए। जिस पर जानकारी के पश्चात् न्यायालय से नकले प्राप्त की जाकर नियत समयावधि में यह अपील प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में पट्टा निरस्त करने के आधार का भी वर्णन किया। जिसमें वर्णित किया कि यह भूमि ग्राम पंचायत से निलामी में कय शुदा भूमि नहीं है। पट्टे में भूमि का कोई मूल्य वर्णित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विपरीत पट्टा जारी किया गया है तथा उस भूमि का पट्टा जारी किया गया है जिसकी मालिक ग्राम पंचायत नहीं थी। साथ ही अन्य तथ्यों का अपनी निगरानी में वर्णन किया गया।

निगरानीकर्ता की निगरानी को दर्ज किया जाकर विपक्षी सुखलाल को तलब किया गया।

विपक्षी सुखलाल की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया गया कि विपक्षी द्वारा सिविल वाद दिनांक 23/4/2014 को सिविल जज साहब सीमलवाडा में प्रस्तुत किया गया तथा सिविल वाद के साथ पट्टे की प्रति भी पेश की गई थी। तब निगरानीकर्ता को उसकी जानकारी दिनांक 22.5.2014 को हो गई थी। निगरानीकर्ता द्वारा पट्टे की जानकारी वर्ष 2014 में होने के बावजूद कोई अपील प्रस्तुत नहीं की, अपील म्याद बाहर है तथा विपक्षी की ओर से निगरानी में अंकित सम्पत्ति को पिता द्वारा कय किया जाना स्वीकार किया गया। पट्टा विधिक प्रक्रिया के तहत प्राप्त किया जाना उल्लेखित करते हुए कथन किया कि सम्पूर्ण भूमि पर विपक्षी का ही कब्जा है। पट्टा सं. 37 के तथ्य मिथ्या अंकित किए गए हैं। ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। पट्टा निरस्त योग्य नहीं है। एवम् अन्य तथ्यों का अंकन किया गया।

न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से मूल पत्रावली तलब किए जाने पर विकास अधिकारी सीमलवाडा के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई जिसमें ग्राम पंचायत रिपोर्ट, पट्टा व रजिस्ट्रेशन की प्रति पेश कर उल्लेखित किया कि प्रार्थी (जो इस प्रकरण में विपक्षी सुखलाल है) के नाम से मूल पत्रावली नहीं मिली है।

दौराने विचारण दिनांक 8/1/2021 को निगरानीकर्ता की ओर से ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसे विपक्षी की ओर से स्वीकार किया गया। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाए जाने का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सरपंच को तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से संशोधित अनवान को प्रस्तुत किया जो रेकार्ड पर लिया गया। सरपंच द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण में जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् विपक्षी सुखलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.9.2020 को उल्लेखित किया कि उनके जवाब को ही बहस मानी जाए तथा निगरानी कर्ता के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया लेकिन उसके पश्चात् पत्रावली कोविड-19 व ग्राम पंचायत से पट्टा पत्रावली तलब करने में चलने से अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पाई। उसके पश्चात् दिनांक 22.2.2021 को बहस समाप्त की गई। प्रार्थी / निगरानीकर्ता के अधिवक्ता

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झुंजरपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंजरपुर
प्रकरण संख्या 02/2019 अनवान श्री सुरेश उर्फ जसवन्त बनाम सुखलाल
निवासी सीमलवाडा जिला झुंजरपुर

द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की तथा दस्तावेजात पेश किए जिसकी नकल विपक्षी अधिवक्ता को दी गई। निगरानी कर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से न्याय निर्णय प्रस्तुत किए गए। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस करते हुए, निगरानीकर्ता के बहस के आधारों को नकारा जाकर कहा गया कि निगरानीकर्ता की निगरानी म्याद में प्रस्तुत नहीं की है जिस कारण खारीज योग्य है।

हमारे द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व विपक्षी की बहस को सुना, प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांतों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी प्रस्तुत किए जाते समय माननीय सिविल न्यायालय सीमलवाडा में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत वाद की नकल, विपक्षी द्वारा दिनांक 1.8.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जिसमें उसके द्वारा पट्टे के दस्तावेज पेश करने बाबत न्यायालय से स्वीकृति चाही, की नकल तथा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत जवाब, विपक्षी के पक्ष में संपादित विक्रय विलेख व पंजीकरण किया हुआ विक्रय विलेख, ठिकाना खास का परवाना जिसमें निगरानीकर्ता के पिता द्वारा भूमि कय किया जाने का उल्लेख है, ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति का प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की है तथा अधिकार पत्र की फोटो प्रति पेश की है। विपक्षी की ओर से अपने जबाब के साथ सिविल जज साहब सीमलवाडा के आर्डर शीट दिनांक 1.8.2019, 16.8.2019, 6.9.2019 व सनद कुमार के बयान की फोटो प्रति पेश की है। उसके बाद निगरानीकर्ता की ओर से लिखित बहस के साथ दस्तावेज माननीय सिविल जज, सीमलवाडा में विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत वाद की नकल, विपक्षी सुखलाल के बयान की नकल, विपक्षी सुखलाल का दिनांक 1.8.2019 का प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत सीमलवाडा के मिसल दिनांक 13.9.2000 की नकल, विपक्षी सुखलाल से सीमलवाडा कोर्ट में की गई जिरह जो निगरानीकर्ता की ओर से की गई, की नकल, सिविल न्यायालय में विपक्षी सुखलाल की ओर से किए गए वाद को विद्धो करने की नकल, विपक्षी सुखलाल का पट्टा, विपक्षी सुखलाल का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज हुआ की नकल, बंटवारानामा, व अधिकार पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ पेश की गई है।

प्रकरण में दो विचारणीय बिन्दु यह है कि--

- (1) क्या प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी समयावधि में है।
- (2) क्या निगरानीकर्ता अपनी निगरानी में अंकित पट्टा जिसको लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसमें विधि, तथ्य, प्रकियात्मक त्रुटि या गलती हुई है, जिससे खारीज योग्य है।

हमारे द्वारा प्रथम बिन्दु पर कि निगरानीकर्ता की निगरानी समयावधि में है, पर सर्वप्रथम विचार किया जाना उचित समझा। इस संबंध में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जैसा कि कथन किया गया कि निगरानीकर्ता को पट्टे की जानकारी विपक्षी सुखलाल की ओर से सिविल जज साहब सीमलवाडा में प्रस्तुत वाद दिनांक 23.4.2014 के बाद जब निगरानीकर्ता द्वारा सिविल जज साहब सीमलवाडा में अपना जबाब दिनांक 22.5.2014 को प्रस्तुत किया, से हो गई थी। यद्यपि इस प्रकरण में सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष प्रस्तुत जवाब रेकार्ड पर नहीं, जिसे विपक्षी की ओर से पेश किया जाना चाहिए था। हमारे द्वारा इस संबंध में विपक्षी सुखलाल की ओर से सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष दिनांक 1.08.2019 को प्रस्तुत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर
प्रकरण संख्या 02/2019 अनवान श्री सुरेश उर्फ जसवन्त बनाम सुखलाल
निवासी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 14 जा.दी.का अवलोकन किया जिसमे उसके द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि भूमि विक्रय विलेख वादी को वृद्ध होने से नहीं मिले थे ऐसे मे दस्तावेज को पत्रावली मे लिया जाकर प्रदर्शित किए जाने का आदेश प्रदान करे जिसका जबाब निगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 16.8.2019 को दिया गया। उपरोक्त दस्तावेज वादी (जो इस प्रकरण मे विपक्षी सुखलाल है)की जानकारी मे प्रारंभ से रहे होंगे लेकिन वह जानता था की दस्तावेज गलत रूप से बनाए है, दुकाने जिस भूमि पर बनी है वह पिता की क्रय शुदा भूमि पर बनी है ईत्यादि जिसके आधार पर स्पष्ट है कि उपरोक्त पट्टा संबंधित दस्तावेज जिसे निरस्त करने के लिए यह निगरानी प्रस्तुत की गई है प्रथम बार दिनांक 1.8.2019 को निगरानी कर्ता की जानकारी मे आए थे। यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी की ओर से सिविल जज साहब सीमलवाडा के न्यायालय मे जो वाद वर्ष 2014 मे पेश किया गया था तथा अपनी साक्ष्य का शपथ-पत्र दिनांक 4.04.2019 को पेश किया गया था उसमे कहीं भी उपरोक्त पट्टा सं० 280 दिनांक 21.7.2005 को कोई हवाला नहीं है। जिसके आधार पर मैं विपक्षी अधिवक्ता की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि निगरानीकर्ता को निगरानी की जानकारी दिनांक 1.8.2019 से पूर्व हो गई हो इस संबंध मे परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 17 मे कपट या भूल के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कथन किया गया है कि परिसीमा काल का चलना तब तक के बिना आरम्भ नहीं होगा जब वादी या आवेदक को उस कपट या भूल का पता न चल जाए। इसके साथ ही निगरानीकर्ता की ओर से इस संबंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2010(1)आर.आर.टी. पेज 167 से 170 माननीय राजस्व मण्डल तथा न्यायिक दृष्टांत 2010(1)आर.आर.टी.पेज 216 से 220 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे मियाद को जानकारी दिनांक से प्रारंभ होना माना तथा यह उद्धरण इस प्रकरण मे पूर्ण रूप से चरखा होते हैं। क्योंकि जिस पक्षकार को जानकारी ही नहीं है वह बिना जानकारी के कानूनी कार्यवाही कैसे अमल मे लाएगा। ऐसी परिस्थिति मे विपक्षी की ओर से किए गए कथन कि निगरानीकर्ता की निगरानी म्याद मे नहीं है, को खारीज करता हूँ तथा निगरानी कर्ता की निगरानी को म्याद मे मानता हूँ। क्योंकि निगरानीकर्ता की जानकारी मे पट्टे का तथ्य दिनांक 1.08.2019 को आने पर उनके द्वारा नियत समयावधि मे निगरानी पेश कर दी गई है।

दूसरा विचारणीय बिन्दु कि, क्या निगरानीकर्ता अपनी निगरानी मे अंकित पट्टा जिसको लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसमे विधि, तथ्य, प्रकियात्मक त्रुटि या गलती हुई है? जिस कारण खारीज योग्य है।

इस संबंध मे हमारे द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात तथा उल्लेखित विधि का अध्ययन किया। जैसा कि पंचायत नियम 1961 की धारा 266 मे उल्लेखित है तथा इस संबंध मे निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2002(1) पेज 63 से लगाकर 69 मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है कि उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत आवंटन को निलामी के जरिए किया जाएगा तथा अपवादिक परिस्थितियों मे ही निजी बातचीत के जरिए विक्रय की जाएगी। लेकिन इस प्रकरण मे ऐसा कोई तथ्य रेकार्ड पर नहीं है कि भूमि की निलामी का प्रयास किया गया हो। क्योंकि सर्वप्रथम तो यह भूमि ग्राम पंचायत की थी ही नहीं। इसलिए उसको

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंजरपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंजरपुर
प्रकरण संख्या 02/2019 अनवान श्री सुरेश उर्फ जसवन्त बनाम सुखलाल
निवासी सीमलवाडा जिला झुंजरपुर

निलामी का अधिकार ही नहीं था और ना ही प्रकरण से भूमि के निलामी का कोई तथ्य प्रकट हो रहा है क्योंकि इस संबंध में विपक्षी सुखलाल के सिविल जजसाहब सीमलवाडा के समक्ष जो जिरह दिनांक 16.08.2019 में हुई है उसमें उसके द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि "प्रदर्श 21 (जिस पट्टे को निरस्त करने यह निगरानी प्रस्तुत हुई है वह दस्तावेज है) में वर्णित सम्पत्ति को मेरे पिता जी ने ठिकाना सीमलवाडा से खरीदी थी" यानि यह स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 को विपक्षी सुखलाल के पक्ष में जारी किया है, वह भूमि ग्राम पंचायत की भूमि नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में नियमों के अर्न्तगत ग्राम पंचायत सीमलवाडा को कोई अधिकार नहीं था कि वह विपक्षी सुखलाल के पक्ष में कोई पट्टा जारी करते। इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत ग्राम पंचायत सीमलवाडा की उस मिसल 1 जो दिनांक 13.9.2000 को दायर की गई तथा दिनांक 21.10.2000 को फैसल की गई का अवलोकन व अध्ययन किया गया। इस मिसल में स्पष्ट रूप से पट्टे में वर्णित सम्पत्ति के निर्माण को लेकर विपक्षी सुखलाल व निगरानीकर्ता व अन्य भाई नवनीत के द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2000 पर स्वयं विपक्षी सुखलाल के हस्ताक्षर भी है तथा इस मिसल के साथ, ठिकाना खास में निगरानीकर्ता के पिता छगनलाल जी द्वारा वर्ष 1948 में भूमि क्रय करने का पुरवाना भी है। मिसल के साथ जो नक्शे संलग्न हैं उसमें विपक्षी सुखलाल, निगरानीकर्ता सुरेश, अन्य भाई नवनीत का हिस्सा स्पष्ट दर्शाया हुआ है। जिसके आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 को जारी किया गया है उस भूमि का एक मात्र मालिक विपक्षी सुखलाल नहीं था एवम् प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात से यह स्पष्ट साबित हो रहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिक नियमों की पालना नहीं की गई है तथा पट्टा नियम 266 राजस्थान पंचायत एवम् न्याय उप.सा. नियम 1961 के अर्न्तगत जारी किया गया है जबकि पट्टा जारी करने की दिनांक वर्ष 2005 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 अस्तित्व में आ गए थे। जो स्पष्ट दर्शित करता है कि ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा विपक्षी सुखलाल को पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 को जारी करते समय विधिक नियमों की अवहेलना की है, तथा विपक्षी सुखलाल द्वारा भी पट्टा जारी करवाते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है, जिन तथ्यों को वह जानता था तथा इसके पीछे विपक्षी का यही उद्देश्य रहा होगा कि वह अकेला सम्पूर्ण सम्पत्ति का मालिक बन जाए और अपने अन्य भाईयों को सम्पत्ति से महरूम कर दें, पट्टा सं. 280 में कहीं भी ग्राम पंचायत के संकल्प सं. का उल्लेख नहीं है, ना भूमि का मूल्य अंकित है। विपक्षी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अधिकार पत्र धारी सनद कुमार द्वारा सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष विपक्षी सुखलाल का कब्जा होना माना है। गवाह सनद के बयान को देखे जाने पर उसके द्वारा इस बात से इंकार किया है कि पट्टे में वर्णित संपत्ति पर सुखलाल का कब्जा हो बल्कि यह कथन किया गया है कि चार दुकानें हैं, दो दुकानों पर सुखलाल का, एक दुकान पर सुरेश का व एक दुकान पर नवनीत के परिवार का कब्जा है तथा इस बात की पुष्टि विपक्षी सुखलाल से की गई जिरह जो सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष दिनांक 16.8.2019 को हुई है जिसमें उसके द्वारा संपत्ति का बंटवारा होना तथा प्रदर्श ए-9 के अनुसार कब्जा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंजरपुर

सुपुर्द किए जाने का कथन किया गया है। प्रदर्श ए-9 सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष प्रस्तुत वह दस्तावेज है जिसके द्वारा निगरानीकर्ता व विपक्षी सुखलाल के पिता छगनलाल द्वारा अपनी संपत्ति को अपनी संतानों के मध्य बांटा गया था। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा जारी पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 जो विपक्षी सुखलाल के पक्ष में जारी किया गया है, के बने रहने से विभिन्न विवादों का जन्म होगा तथा प्रथम दृष्टया उपरोक्त पट्टा ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा गलत रूप से विधिक नियमों की अवहेलना करते हुए, आज्ञापक नियमों की अवहेलना करते हुए जिसमें प्रकिया संबंधी त्रुटि भी स्पष्ट प्रतीत हो रही है तथा विधि एवम् तथ्यों की भी भूल की गई है, प्रमाणित व दृष्टिगोचर हो रहा है। मेरी विनम्र राय में ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है। इस पट्टे की कोई पत्रावली मिसल ग्राम पंचायत सीमलवाडा के पास उपलब्ध नहीं होना संदेह को और अधिक गहरा कर देती है। इन सब परिस्थितियों, तथ्यों, न्याय दृष्टांतों की रोशनी में ग्राम पंचायत सीमलवाडा के उपरोक्त आदेश जो पट्टे पर मात्र दिनांक 20.7.2005 अंकित किया जा चुका है को खारीज निरस्त किया जाना उचित पाता हूँ तथा ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा जारी पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 जो विपक्षी सुखलाल पिता छगनलाल पण्ड्या, निवासी सीमलवाडा के पक्ष में जारी किया गया है को खारीज और निरस्त करता हूँ। निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार को जाकर ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा जारी पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 जो विपक्षी सुखलाल पिता छगनलाल जी पण्ड्या निवासी सीमलवाडा के पक्ष में जारी किया गया है, को खारीज और निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत सीमलवाडा को तहरीर जारी हो तथा ग्राम पंचायत सीमलवाडा से तलब पत्रावली मय इस निर्णय प्रति के प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

